

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अमिलेख संलग्न किये जाने हैं)

FORM-I
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli
Government Of Uttarakhand

No.....

Dated...21-9-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 40.8916 ha of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway & Infrastructure Development Corporation Limited "for Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000 in Chamoli District in the State of Uttarakhand."**


It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 40.8916 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.3.0:1...to annexure.3.0:4;
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed the and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: As above


जिला अधिकारी
चमोली


जिला अधिकारी
(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli


प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

District:- Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional for dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. SWATI BHADORIYA**, District Magistrate Chamoli, on dated 21.9.2019 at time 03:45 at Chamoli in which application claiming rights in Forest Land area measuring 40.8916 ha. forest land for **Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000 in Chamoli District in the State of Uttarakhand** under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Chamoli Dispetihar

Dated 21/9/2019

hns
प्रिलासना बरुवा मजि

हस्ताक्षर
जिला अधिकारी
(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli

हस्ताक्षर
प्रणालीय वनाधिकारी
प्रणालीय वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित राइक का चौड़ीकरण एवं सड़कीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 26.6.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यावाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवान-5

उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री देवान-5 उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. श्री 3मं देवान-5 उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3. श्री 4मं देवान-5 सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4. श्री 5मं देवान-5 बी0 डी0 सी0 क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सड़कीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सड़कीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

(प्रमाण) 01/07/2019
मुख्य प्रमाण कक्ष

देवी देवी
क्षेत्र पंचायत सोमला
दि0स0 कर्णप्रयाग (वजोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली

दमयन्ती
दमयन्ती मैथुरी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत उत्तर
वि0सं0-कर्णप्रयाग चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 26/8/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यावाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बुशरा अंसारी

उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री बुशरा अंसारी उप जिलाधिकारी
2. श्री अमरेंद्र कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री राजेश कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री अमरेंद्र कुमार बी0 डी0 सी0 क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम समा/पंचायत दावा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

(सहस्र) 10/11/2019

10/11/2019

10/11/2019

26/8/2019
अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
(चमोली)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 19/11/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री

उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री जयलाल कुमार - उप जिलाधिकारी
2. श्री अमरेंद्र कुमार - उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री राजेश कुमार - सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- श्री 025 नगी - वी0 डी0 सी0 क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

(11/01/20) 11/01/20 01/01/20

20/01/20 नगी
संघ पंचायत सोनला
दि0ज0 कर्णप्रयाग (नगीली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसील:- कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपद:- चमोली 4/9/19

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अधीक्षक
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील:- कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपद:- चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 384.400 से कि0मी0 399.000 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - कर्णप्रयाग

नगर पालिका का नाम:- कर्णप्रयाग

वार्ड नं0 -

तहसील:- कर्णप्रयाग जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 384.400 से कि0मी0 399.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 1.330 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.3995 हे0 सिविल/वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 7.7295 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 01/5/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/ Pran
नगर पालिका अध्यक्ष
नगर पालिका परिसर कर्णप्रयाग
चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - नाकोट (करसाबी), डमटा

ग्राम पंचायत का नाम:- नाकोट

तहसील:- कोरप्रयाग जिला:- कोशी

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 8.04.19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-324

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - कादू कालेश्वर

ग्राम पंचायत का नाम:- कालेश्वर

तहसील:- करीयप्रयाग जिला:- चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 10/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - जयकन्डी, ग्वाड़

ग्राम पंचायत का नाम:- जयकन्डी, बड़सोली

तहसील:- कर्णप्रयाग जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ्ढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - उत्तरी

ग्राम पंचायत का नाम:- उत्तरी

तहसील:- रुद्रप्रयाग जिला:- रमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ्ढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित



प्रारूप-30.4

ग्राम का नाम - उत्तरी

[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत सुपुल
रस्ता नं. २२७/१
बिलासपुर
२६/११/२०१७
६६० बिलासपुर (बिलासपुर)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - लंगाख, निवाडी, उमशकोटी रूफ बैडानू

ग्राम पंचायत का नाम:- लंगाख

तहसील:- कर्णप्रयाग जिला:- चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ़ीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - ढुगलवाली, चिरोली, हाडाकोटी, नौलीतली

ग्राम पंचायत का नाम:- ढुगलवाली

तहसील:- चमोली जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/05/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित

(Handwritten Signature)



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - सोनला, रुद्रप्रयाग, पुरसाड़ी

नगर पालिका का नाम:- रुद्रप्रयाग

वार्ड नं0 -

तहसील:- चमोली जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 05/05/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमरा
अध्यक्ष
ह0/ नगर पंचायत रुद्रप्रयाग
नगर पालिका रुद्रप्रयाग
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - मैहणा

ग्राम पंचायत का नाम:- मैहणा

तहसील:- चमोली जिला:- चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0 /
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - सैमच बाजबागढ़, रोपा

ग्राम पंचायत का नाम:- रोपा बाजबागढ़,

तहसील:- कोली, जिला:- कोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 15/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0 /
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

ह0
दिनांक 15/5/2019

ग्राम पंचायत रोपा बाजबागढ़

प्रारूप-30.4

ग्राम का नाम - ~~कुहड़~~ सैमच बाजबाग, रोपा
ग्राम पंचायत का नाम:- " रोपा बाजबाग "

ह0 / -
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

हो..... गीता देवी
दिनांक 13/5/2019

4-21727

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - कुसाहू गाव, गोलिफ

ग्राम पंचायत का नाम:- गोलिफ

तहसील:- चमोली, जिला:- चमोली -

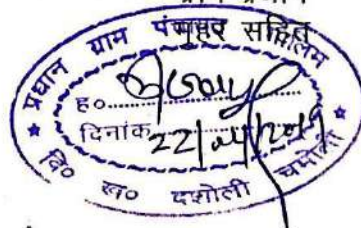
उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 22/11/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परस्परगत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - भूमला लगगा खेनूरी

ग्राम पंचायत का नाम:- खेनूरी

तहसील:- चमोली जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 04/03/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - जाडी
ग्राम पंचायत का नाम:- जाडी

तहसील:-चमोली जिला:-चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 25/6/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

ग्राम पंचायत का नाम:- नाडी

मान
हेत

प्रधान ग्राम पंचायत मन्डल
८० किलो
दि. 25/6/2019

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - पाखी, जलवाट

ग्राम पंचायत का नाम:- पाखी

तहसील:- जोशीमठ जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 02/04/19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ़दीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - हंगली तल्ली

ग्राम पंचायत का नाम:- हंगली तल्ली

तहसील:- जोशीमठ जिला:- कोशी -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ़दीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 21/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/- 21/5/2019
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - टंगणी मल्ली

ग्राम पंचायत का नाम:- टंगणी मल्ली

तहसील:-डोशीमह जिला:-चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढ़ीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 1/03/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित



प्रारूप-30.4

ग्राम पंचायत का नाम:- टुंगोली मल्की

[illegible]

ह0 /-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - मौलीवाड

ग्राम पंचायत का नाम:- गण्डा

तहसील:- जोशीमठ, जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 02/03/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर-पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित



प्रारूप-30.4

ग्राम पंचायत का नाम:- जगाई

[illegible]

६०/-

ग्राम प्रधान

महेश सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-50) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - नगर पंचायत पीपल्कोटी, बाटूला, गाढेश, संगरुला, बिरही
नगर पालिका का नाम:- पीपल्कोटी, नौख, क्षेत्रपाल
वार्ड नं0 -

तहसील:- चमोली जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 11.03.19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0 [Signature]
नगर पालिका अध्यक्ष
[Stamp]
नगर पंचायत
पीपल्कोटी (चमोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एन0-50) के कि0मी0 390.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सड़कीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक 07/03/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - वादूला, गढोरा, संगपला, नौरख, क्षेत्रपाल, विरही
नगर पालिका का नाम:- पीपलकोटी
वार्ड नं0 -

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अश्विनी नुव्वर	
2	लीला आदिगाला	
3	चन्द्र मोहन दलवाल	
4	हरीपन्न नुव्वर	
5	लीला वैष्णव सभासद गडोरा	
6	निरन्जित खन्ना	
7	गोपबन्धु सभासद	
8	धर्मेन्द्र सिंह सभासद	
9	कमलेश्वर पवार	
10	रमेश शर्मा	
11	अश्विनी शर्मा	
12	दीपक शर्मा	
13	कुन्दन सिंह शर्मा	
14	नौरजपाल सिंह (गणद)	
15	पवन शर्मा	
16	मन्जू देवी (सभासद)	
17		
18		
19		
20		
21		

ह0/07/19
नगर पालिका अध्यक्ष
मुख्यालय
नगर प्रशासन
पीपलकोटी (बमोली)